

- \*विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 को राधाकृष्णन कमीशन भी कहा जाता है
- \*स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित था
- \*राधाकृष्णन आयोग ने यूजीसी की स्थापना की सिफारिश की
- \*1953 में यूजीसी की स्थापना हुई और 1956 में इसे संवैधानिक मान्यता दी गई
- \*ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया
- \*राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर 1948 में एनसीसी एंड 1969 में एनएसएस की स्थापना हुई
- \*उच्च शिक्षा स्तर पर सहशिक्षा यानी को-एजुकेशन की सिफारिश की
- \*प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की सिफारिश राधाकृष्णन आयोग ने की
- \*भारत में 42 वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची पर लाया गया
- \*माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 को मुदालियर कमीशन भी कहा जाता है
- ,\*मुदालियर आयोग का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा था
- \*बहुद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव ताराचंद समिति ने दिया
- \*मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के मुख्य दो उद्देश्य बताएं जिनमें लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास एवं नेतृत्व शक्ति का विकास
- \*मुदालियर आयोग ने 5+ 6 + 3 की संरचना का सिफारिश की
- \*मुदालियर आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को 7 भागों में बांटा
- \*राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 को कोठारी आयोग भी कहा जाता है
- \*कोठारी आयोग संपूर्ण भारतीय शिक्षा के संपूर्ण स्तर से संबंधित था
- \*कोठारी आयोग के प्रतिवेदन का शीर्षक **शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति** है
- \*कोठारी आयोग में अपने प्रतिवेदन के शुरुआत में लिखा है **देश का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है**
- \*कोठारी आयोग में **शिक्षा का बजट 6% करने की सिफारिश की**
- \*विद्यालय संकुल यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की सिफारिश कोठारी आयोग ने की
- \*शिक्षा के उद्देश्यों में पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग ने दिया
- \*कोठारी आयोग में वरिष्ठ विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया

\*15 से 30 वर्ष की आयु के प्रौढों के लिए प्रौढ शिक्षा की सिफारिश की

\*राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के विस्तार पर रोक एवं उन्नयन पर बल दिया

\*स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 को आई